PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, I beg to announce that the Government Business in this House for the week commencing 2nd March 2010 will consist of:-

(I) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(II) General Discussion on the Budget (Railways) for 2010-11.

SHORT DURATION DISCUSSION - Contd.

Situation arising out of continued rise in prices of essential commodities in the country

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे इस ज्वलंत समस्या पर बहस करने का मौका दिया है।

महोदय, यह जो महंगाई का मुद्दा है, मुद्रास्फीति का जो मुद्दा है, यह कोई academic discussion के लिए नहीं है। इसका सीधा प्रभाव हमारे देश के करोड़ों गरीबों के ऊपर पड़ता है, working poor के ऊपर पड़ता है और middle class के ऊपर पड़ता है। आप जानते हैं कि हमारे देश के 90 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में हैं जिनके लिए महंगाई के बारे में कोई dearness allowance या कोई compensation का प्रावधान नहीं है और इसलिए जब महंगाई बढ़ती है तो उसका सीधा-सीधा impact उन पर पड़ता है। उसक एक सामाजिक पहलू भी है। गरीबों पर उसका सबसे बड़ा असर पड़ता है। गरीबों में और समाज में जो महिलाएं हैं, ऐसा भी होता है कि परिवार के अन्दर जो असमानताएं होती हैं, उसमें महिलाओं के ऊपर जो बोझ पड़ता है वह इस आंकड़े से भी प्रतिबिम्बित होता है कि malnutrition की figures में पौष्टिक आहार से सबसे अधिक वंचित इस देश की महिलाएं हैं और इस देश की बच्चियां हैं। उसमें मैं दलित को भी जोड़ूंगी और मैं आदिवासी को भी जोड़ूंगी, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो उनके ऊपर एक disproportionate burden होता है। इसीलिए मैं कहती हूं, सभापति महोदय, कि यह academic नहीं है, यह हमारी जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है और इसीलिए मैं खेद प्रकट करती हूं कि आज तक महंगाई के सवाल पर सिर्फ बहस ही बहस रही है, लेकिन उसमें जिस नीति-परिवर्तन की जरूरत है, जो सरकार अपने course-correction की बात सोचे, वह एकदम नहीं है। उसका कारण यह है कि आज तक Central Government अपनी इस विफलता या असफलता की जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और आप केवल blame game करेंगे तो फिर इस देश की जनता आपसे क्या उम्मीद कर सकती है? हम राम भरोसे रह जाएं कि आज बारिश होगी और हमारी फसल अच्छी होगी तथा जब वह बाजार में आएगी तो इससे महंगाई कम हो जाएगी। अगर एक आधुनिक देश की जनता की यही हालत होती है तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर यह प्रश्नचिह्न लगता है। इसीलिए मैं सरकार से यह अपील करना चाहूंगी कि अगर वह वाकई महंगाई को रोकना चाहती है - इसे आप कोई प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइए। आम आदमी के बारे में जो आप कहते हैं, अगर वाकई में वह आप करना चाहते हैं, महंगाई को रोकना चाहते हैं, तो नीति-परिवर्तन कीजिए। आप पुराने दिनों के बारे में, आत्मनिर्भर के बारे में सोचिए। हमारे देश का मुख्य सवाल self-reliance in food

production है। आज हम कहां हैं? हमारे साथी, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूं। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर का सार हमारे देश का Achilles' heel है, यानी सबसे कमजोर है। यह क्यों कमजोर है? किसान की मेहनत की कमजोरी नहीं है। वह इसलिए कमजोर है, क्योंकि आपने food production के लिए आत्मनिर्भरता छोड़ दी। आप ग्लोबलाइजेशन और neo-liberal policies के चक्कर में माकेर्ट मोह के शिकार हो गए हैं और इसीलिए हिन्दुस्तान का किसान आज पीड़ित है। हिन्दुस्तान का किसान आत्महत्या कर रहा है। हिन्दुस्तान के किसान हमारे देश के Achilles' heel नहीं हैं। आपकी नीति हमारे देश की Achilles' heel है, आप उसको बदलिए ताकि हम आगे बढ़ें।

सर, मैं सेंट्रल पॉलिसी के बारे में कहती हूं। मैं मानती हूं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। हम उसे स्वीकार करते हैं। आज 10 स्टेट कुछ food relief देने के लिए गवर्नमेंट्स-सब्सिडी दे रहे हैं। वे और भी सब्सिडी दे सकते हैं, यह मैं मानती हूं। मैं यह भी मानती हूं कि फार्म, गेट, मंडी और रिटेल प्राइसेज़ में जो गैप है, उसमें निश्चित रूप से hoarding, speculation है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की एक जिम्मेदारी है, मैं मानती हूं, लेकिन आज हमारे देश में कौन-सा वातावरण तैयार हो रहा है? क्यों speculators का field day है? क्यों hoarders का एक field day है? क्यों profiteers का field day है? अगर आप उसको देखेंगे तो मैं यह मानती हूं कि यह वही neo-liberal framework है, जिसके कारण आपने self-reliance को छोड़ दिया है। Food production को छोड़ कर आप export-oriented corporate-driven agriculture पर जाना चाहते हैं। अगर आपको इस प्रॉब्लम का long-term solution ढूंढना है तो आप इस नीति को बदलिए, आप agriculture पर जोर दीजिए, आप rural development, infrastructure development पर जोर दीजिए। केवल Missions का नाम देकर आप प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते हैं। Pulses Mission, Oilseeds Mission, Mission पर Mission, लेकिन Mission का एक मुख्य सवाल यह है कि इसके लिए कौन accountable है कि आज भी pulses में इतनी कमी है? यह किसकी जिम्मेदारी है कि आज भी हमें oilseeds import करना पड़ता है? उसको आप रेखांकित करके self-reliance पर दोबारा आइए, तभी हमारी long-term food security होगी और तभी long-term prices के बारे में आप एक countervailing impact ला सकेंगे।

सर, मेरे पांच-छः प्वायंट्स हैं। एक fertilizers के बारे में है। इस सरकार का पार्लियामेंट के प्रति रवैया क्या है? क्या पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है? पार्लियामेंट सत्र के तीन-चार दिन पहले आप यह एलान कर देते हैं कि हम fertilizers के दाम बढ़ा रहे हैं। किसान मर रहे हैं। आज आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या दो लाख हो चुकी है। किसान drought और floods का शिकार बन रहा है और उसके ऊपर आपने यूरिया fertilizer के दाम 10 परसेंट बढ़ा दिये! आपकी nutrient-based fertilizer के बारे में क्या नीति है? आपने deregulate करने का फैसला करके international prices जो ऊंची है, उसके साथ आप link-up कर रहे हैं? यह क्या तरीका है? अगर आप पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं तो आप इस Fertilizer Price hike को withdraw कीजिए। आप इसको खत्म कीजिए। जब हम लोग चांद पर पहुंच सकते हैं तो क्या हम fertilizer में self-reliant नहीं बन सकते?

सर, हमारे सात Public Sector Units हैं। आज सातों Public Sector Units बंद हैं। क्यों? UPA-I के समय हमें पता है, Central Government के जो मुख्य Public Sector Units थे, उनके बारे में हमने UPA-I को पूरी चार्ट दी। उन्होंने यह तय कर लिया कि three fertilizers units को कितने सौ करोड़ रुपये देकर चालू करेंगे, लेकिन आज तक उन्हें चालू नहीं किया गया, वे आज तक बंद हैं। आप fertilizers के दाम बढ़ा कर किसानों का बोझ और बढ़ाना चाहते हैं। यही Central Government's policy है जो इस price rise को feed करती है। इसलिए आप fertilizers के दाम को कम कीजिए, उस price rise को खत्म कीजिए। आप सातों Public Sector Units को Self-reliance के आधार पर खोल कर imports को कम कर सकते हैं। यह मेरी पहली बात है। सर, फर्टिलाइज़र के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं, क्योंकि हमारे साथी माननीय शिवा, मैंने देख लिया है उनको, कि यह बात है coalition politics की, सरकार की नीति क्या है। Sir, it is like, when you toss a coin and say, "Heads, I win; tails, you lose". This is the Congress brand of coalition politics. When it suits me, then, I would say, "No, no. Sugar Ministry is not in my control. I can't do anything about it." But, when it is fertilisers and the DMK Minister takes a strong stand saying that they don't want prices of fertilisers to be raised, then, what happens to coalition politics? So, please, don't try to fool the people as far as coalition politics is concerned. Look at the people. The paramount concern must be the people. I congratulate my friend from DMK and I hope that they are going to remain firm in their stand. I want to tell my dear friend, Siva, that Governments can manipulate and survive, but, farmers cannot survive. Therefore, keep firm to your stand.

दूसरी बात मैं शुगर के बारे में कहना चाहती हूं। सर, यह scandal है और मैं साफ कहती हूं, मैं स्टेटमेंट करती हूं इस हाउस में कि यह scandalous record है सरकार की नीतियों का। लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने बिल्कुल सही कहा है कि यह manipulated policies हैं और manipulated policies कहां-कहां, कैसे-कैसे हुई हैं, मैं चाहती हूं कि इसके बारे में एक व्हाइट पेपर हो और उस व्हाइट पेपर के आधार पर ये तमाम मुद्दे देश के सामने लाए जाने चाहिए। वे मुद्दे क्या हैं? पहला, सभी जानते हैं कि जो गन्ना उत्पादक किसान है, उसके साथ क्या-क्या होता है। जब गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है, दाम गिरता है तो वह खेतों में अपना गन्ना जला देता है। फिर सोचता है कि अगले साल मैं क्या करूं और वह कहता है कि इस साल मैं गन्ना पैदा ही नहीं करूंगा। वह कुछ और पैदा करता है, लेकिन उस साल देखता है कि कितना मुनाफा किसी और का बन रहा है, उसका एरियर्स रह जाता है। तो पहली बात है कि आप शुगर प्राइस के बारे में गन्ना किसान को अपनी नीति का केन्द्र बनाकर उसकी मदद करें, उसकी रक्षा करें, तब इस cyclical वाली बात है, जो बात यहां बार-बार आती है, उस पर आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि ये बड़े अजीब कुछ आंकड़े हमने देखे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर का जो नोट है और उसके बाद डा. मुरली मनोहर जोशी जी की लीडरशिप में स्टेंडिंग फाइनैंस कमिटी की जो रिपोर्ट है, जिसमें इन्फलेशन प्राइसिस का उन्होंने दिया है। सर, अभी क्या है 2008-09 में 20 प्रतिशत गन्ने का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम हुआ लेकिन चीनी का उत्पादन 44 प्रतिशत कम हुआ। 20 प्रतिशत कम हुआ गन्ने का

उत्पादन और 44 प्रतिशत कम हुआ चीनी का उत्पादन! अब जब हमने यह निकाला कि क्या हर बार ऐसे होता है, तब पता चला कि ऐसे नहीं होता। जब shortages होते हैं, तब कुछ diversion जरूर होता है, लेकिन इतना diversion और रिकवरी रेट इतना बढ़ा जाए upto 20%, यह आज तक कभी नहीं हुआ, हमने सारे आंकड़े देखे हैं। जब हमने सरकार का इस मुद्दे का दलील देखा कि क्या है, तो उनके नोट में लिखा है कि यह खांडसारी और गुड़ के लिए divert हुआ, लेकिन इतना diversion नहीं होता। किसने divert किया, किसने लिया? इस प्ररिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो इन सालों में सभी पीड़ित थे, कौन पीड़ित नहीं था? बड़ी शुगर मिल कम्पनीज़। Sugar farmers पीड़ित, consumer पीड़ित, राशन की दुकान खाली, लेकिन कौन-कौन जुग-जुग जी रहा था - 33 शूगर मिल कम्पनीज़, जिनका मुनाफा 2000 प्रतिशत बड़ा! 30 करोड़ से 900 करोड़ केवल एक साल में और आज तो ऐसी भी शुगर कम्पनीज़ हैं, इनका एकदम इतना बन गया है कि ब्राजील में भी एक नहीं, दो-दो शुगर कम्पनीज़ खरीद रहे हैं। यह कैसे होता है? इसलिए मैं कहती हूं कि जब shortage थी, तो सरकार ने क्या किया कि उन्होंने buffer stock नहीं बनाया, हां, कुछ stock था लगभग 105 लाख टन, which was carried over for the next year, लेकिन वह deplete हो गया, क्योंकि आपको मालूम था कि उस साल shortage होने वाली है, यह forecast था कि उस साल shortage होनी है, लेकिन आपने buffer stock नहीं बनाया, आपने क्या किया? श्री विलासराव जी जानते हैं, वे उस समय महाराष्ट्र में थे, वहां आपने exports को incentivize किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1,350 रुपए प्रति टन सब्सिडी दी, महाराष्ट्र की बहुत दयालु सरकार ने उसके ऊपर एक हजार रुपए प्रति टन की सब्सिडी दी, यानी 2,350 रुपए प्रति टन की सब्सिडी एक्सपोर्ट करने के लिए दी गई। फिर दिसम्बर, 2008 तक आपने एक्सपोर्ट किया, अचानक जनवरी, 2009 में सरकार कुंभकर्ण की नींद से उठ गई, उसे पता चल गया कि shortage होनी है, इसलिए इंपोर्ट करो, कैसे इंपोर्ट करो - without duty, without tax इंपोर्ट करो और इंपोर्ट को incentivize करो। यह scandal नहीं है तो क्या है? आज कंज्यूमर को चीनी के लिए 40 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो देने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि आपकी शूगर नीति गलत है और शूगर नीति की accountability को आप रेखांकित कीजिए और इस पर एक White Paper पार्लियामेंट में लाइए। अगर आप हमारा सहयोग चाहते हैं, तो इस पर पार्लियामेंट की एक Joint Committee बनाइए, ताकि इस देश की जनता अगले साल इससे बच सके, यह मेरा सुझाव है।

सभापति जी, अब मैं Public Distribution System यानी जन वितरण प्रणाली पर आती हूं। अरुण जी ने बहुत सारे सरकार के lame excuses और fake alibis पर टिप्पणी की, लेकिन हमारी नज़रों में इसकी मुख्य विफलता का कारण यह है कि आपने किस तरह step-by-step राशन प्रणाली को चौपट किया है। आप चाहते हैं कि इसके लिए जनता दोषी है और जनता की बढ़ी हुई मांग के कारण आज मांग बढ़ रही है। हमारे साथी ने REGA का नाम लिया, जरा सोचिए, जरा प्रैक्टिकल होकर, जमीन पर उतरकर हम लोग बात करें, तो अच्छा होगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में इतना बढ़िया REGA चल रहा है, लेकिन फिर भी average is 50 to 60 days in a year. 5 लोगों के परिवार में कितना पैसा बनेगा? अगर आप परिवार के सदस्यों की संख्या 5 मानें, तो कुल मिलाकर हर सदस्य का कितना पैसा बनता है - 3 रुपए प्रतिदिन। आप कहते हैं कि 3 रुपए प्रतिदिन मिलने से मांग इतनी बढ़ गई और आप REGA की बात कर रहे हैं। एक manual labour को सुबह से रात तक काम करने के लिए कम से कम 2,500 कैलोरीज़ की जरूरत है। मैं आपसे कहती हूं कि आपके पास जरूर कोई जादू की छड़ी

होगी, जिससे आप उस REGA worker को, 2,500 कैलोरीज़ तीन रुपए में खरीदकर दे देंगे। इसलिए मैं कहती हूं कि यह गलत alibi और गलत excuse है। जनता की purchasing power घटी है तथा hoardings and speculations बढ़ी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस PDS को चौपट किया है। इस देश में कौन सा आदमी गरीब है? उसके poverty estimates क्या हैं? तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट है, सभी ने कहा कि गरीबी बढ़ी है, हम उस methodology से सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि गरीबी बढ़ी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आप BPL को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आपने क्या किया? आपने पूरे APL allocation को खत्म किया। साथियों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में 75 परसेंट APL allocation कट गया। आज आप 20 मिलियन टन का buffer stock बता रहे हैं, we are very happy कि 20 मिलियन टन का buffer stock है, लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप bulk consumers को सब्सिडी पर चीनी दे रहे हैं, आप बड़े chocolate manufacturers को चीनी दे रहे हैं soft drink manufacturers को दे रहे हैं और इस तरह करीब 65 परसेंट चीनी buld consumers ले रहे हैं। आप wheat को bulk consumers को दे रहे हैं। आप स्टेट्स को जहां 8 रुपए प्रति किलो देते थे, वहां आज आप स्टेट्स को 15 रुपए किलो दे रहे हैं। इसका यह नतीजा हुआ कि आपने 20 लाख टन दिया, लेकिन स्टेट्स ने 1.17 लाख टन उठाया। स्टेट्स जानती हैं कि आप उनके हाथों से APL के लिए दाम बढ़ाना चाहते हैं, वे नहीं करने वाले हैं। APL का allocation वापस दीजिए, यह जो पीडीएस के बारे में पूरी नीति है, उसमें हम चुनौती के साथ कहते हैं कि आप सब्सिडी को कम कर रहे हैं। आपकी पॉलिसी सब्सिडी कम करने की है। आपको Food Security Legislation के लिए economist ने 1,20,000 करोड़ रुपए सालाना का estimate किया। अरे वाह! इतना पैसा। लेकिन उसी एक साल में आप अमीरों को tax concession पर चाल लाख करोड़ रुपए सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन Food Security Legislation के लिए आप क्यों चुप हैं? Presidential Address में time framework क्यों नहीं दिया? इसलिए मैं कहती हूं, Sir, change your policy regarding PDS; make it universal. Bring a Food Security Legislation. That will be the major impact against prices. It is the countervailing weight over the market. Our own history shows us that. Please do that. That is what I say.

One more point I want to make. I am sure, Vilasraoji will be interested to know this. There is a letter written, Sir. Copies have been circulated to many Members of Parliament, to the UPA Chairperson. What does it say? We are saying there is no grain in the ration shop. हम बोल रहे हैं कि राशन शॉप है, shortage है। महाराष्ट्र ने नीति तय की कि कुछ industrial units जो liquor बनाएंगे, उनके लिए वह 1.4 मिलियन लाख टन grains प्रति साल divert करेंगे।

SHRI PENUMALLI MADHU (Andhra Pradesh): Ten per cent of the total production.

श्रीमती वृंदा कारत : ये factory owners कौन हैं? यह आरटीआई द्वारा पता चला कि ये सब वहां के जितने बड़े political leaders हैं, उनके लड़के हैं या उनके पोते हैं या उनके जमाई हैं और जो भी हैं और सिर्फ यहीं नहीं बल्कि उन सभी को per factory पचास करोड़ रुपए का incentive भी दे रहे हैं। Please don't do this, Sir. Please don't divert foodgrains for liquor and alcohol. जिनको पीना है, वह पीए, लेकिन कम से कम हमारे देश के फूड सेक्यूरिटी के आधार पर ऐसा न करें। सर, इसलिए मैं आपके माध्यम से श्री विलासराव देशमुख जी से अपील करती हूं कि मैं यह आरटीआई की कॉपी आपको देती हूं, आप kindly इसके बारे में देखकर इसको वापस कीजिए। यही महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा होगा। Sir, future trade. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : You are running out of time.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I have three points more and I will finish them very quickly. सर, मैं फ्यूचर ट्रेड के बारे में कहना चाहती हूं। हमारे साथी ने सही कहा है कि जो speculative capital है, आज यह निश्चित रूप से spot prices पर उसका असर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्लियामेंट स्टेंडिंग कमिटी ने इस पर पूरी स्टडी करके उसकी relation दिखा दी है। उसमें हमारे कांग्रेस के साथी भी थे। उन्होंने भी कहा। लेकिन क्या अजीब बात है कि between the two Governments, in May, just before this Government was going to be sworn in, in a most clandestine way, the ban on future trade of wheat was removed. Why? आपने wheat पर पाबंदी को क्यों remove किया? आपने ban लगाया, क्योंकि यह पार्लियामेंट की मांग थी और स्टेंडिंग कमिटी की मांग थी। Secretly, when the Government was not yet formed, you removed it. Why is that done? What is the explanation for this? Kindly inform the House. We would also like to know what was the sudden urgency for you to remove the ban on wheat. Was it not, once again, to help speculation? Was it not, once again, to help those speculators and those hoarders who were waiting for such a removal on the ban? Haldi, potatoes. Why should they be listed? Why should these be traded, Sir? जब हमारे में इतना malnutrition है, तो ये सारी आवश्यक चीजें मुनाफे के लिए क्यों हैं? इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि यह जो फ्यूचर ट्रेड की नीति है, इसको बदलिए, इस पर पाबंदी लगाइए। इसमें पूरे देश की और पार्लियामेंट की पूरी सहमति है। इसको करके आप देश को बचाइए। Sir, the two more points. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : You kindly conclude. You have run out of your time.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, just two more points. I want to finish them very quickly.

सर, मैं tax or duties के बारे में कहना चाहती हूं। अभी "कीरित पारिख कमिटी" आने वाली है। यह तलवार लटकी हुई है। सरकार को कहना चाहिए कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि हम consider

कर रहे हैं। Inflation and speculation; once again, inflationary trends. Once again, people think: Ah, ah, petrol/diesel is going to rise! That has a cascading impact. Your own report says that. The Leader of the Opposition has very correctly mentioned about the whole regime ot excise and duties. But I just want to give you one example. Don't blame the States for this because it is your policies and your tax structure. Out of every rupee that we spend on a litre of petrol, the production cost and the import cost is 48 paisa. Out of every rupee that we spend on petrol, 34 paisa to 36 paisa is because of Central Government taxes. मैं कहती हूं कि उसको कम कीजिए, जनता को कुछ राहत दिलवाइए और उसका जो casceding effect है....

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

श्रीमती वृंदा कारत : सर, मेरा जो आखिरी प्वाइंट है, वह वैट के बारे में है। हमने बहुत सुना कि स्टेट्स वैट लगा रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के भाषण में भी मैंने देखा कि स्टेट्स वैट लगाएं, लेकिन हमने हकीकत को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की। जो 32 प्रदेशों में imported sugar है, 22 स्टेट्स में वह ज़ीरो वैट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमने वैट कमेटी की रिपोर्ट देखी। अब यह पता चल रहा है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को वैट पर compensation देना नहीं चाहती, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि हर वैट का स्लैब बढ़ाओ, चार परसेंट से पांच परसेंट बनाओ। यह हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की दोहरी नीति।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I am just concluding. This is my last point. Yes, it is price rise because VAT is very much connected with price rise. Take, for example, rice, in Andhra Pradesh, it is four percent; in Maharashtra, it is four per cent; in West Bengal, it is zero. Take green-gram, channa dal, milk, wheat and salt. In Andhra Pradesh and Maharashtra, it is four per cent, four per cent and four per cent. In West Bengal, it is zero. ...(**Time-bell**)...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, my concluding point is that as far as taxes, duties and VAT are concerned, please take the responsibility of ensuring that the States don't put such VAT, which can be done if you compensate the States with the compensatory amount you have assured once the VAT regime was introduced in this country, because this has a direct impact on the prices of essential commodities.

Thank you so much for your patience and I hope that the Government will take note of these points and make a course correction.

श्री ब्रजेश पाठक (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, आज महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में काफी जद्दोजहद के बाद चर्चा शुरू हुई है। होना तो यह चाहिए था कि जब सम्पूर्ण विपक्ष मांग कर रहा था कि सदन में इस पर चर्चा नियम 167 के तहत हो, तो वही होती। चर्चा में जो निष्कर्ष निकलते, उसमें सरकार पर जिम्मेदारी भी तय

होती, क्योंकि उसे मतदान होना था, लेकिन दो दिन के गतिरोध के बाद आज हम सब लोगों ने तय किया कि पूरे देश को तो यह जानना और सुनना चाहिए कि आखिर यू.पी.ए. की गवर्नमेंट, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, वह देश के लोगों को क्या देना चाहती है, देश के गरीबों के सामने क्या रूपरेखा रखना चाहती है? इसलिए आज हम लोगों ने इस मुद्दे पर बहस करना शुरू किया।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले नारा दिया था कि "कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ" और उनकी सरकार बन गई। सरकार बनने से पहले जब 14वीं लोक सभा का कार्यकाल था, तो इन्होंने चुनाव से पहले तेल की कीमतों में कई बार कमी की। हमें अच्छी तरह याद है कि तीन बार तेल के दामों में कमी की गई, लेकिन जब चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यू.पी.ए. की गवर्नमेंट बनी, तो इन लोगों ने बजट से पहले ही, सत्र शुरू होने से पहले ही तेल के दामों में कई गुना वृद्धि कर दी। महोदय, तेल आम आदमी के साथ इस कदर जुड़ा हुआ है कि तेल के दाम जब बढ़े, तो भाड़ों में वृद्धि हुई। और जब भाड़े में वृद्धि हुई तो उसका सीधा असर खाद्यान्न पर पड़ा, आम आदमी की जरूरतों पर पड़ा और आम आदमी की कमर बुरी तरह टूट गई।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

माननीय उपसभापति महोदय, आज यूपीए की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रही है, गरीबों को राहत देने के सवाल पर अपनी जिम्मेदारी से बचकर राज्य सरकारों पर दोष मढ़ने का काम कर रही है जबकि सच्चाई यह है कि यूपीए के घटक दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में भले ही न हों, लेकिन दूसरे राज्यों में यूपीए के घटक दलों की सरकारें हैं। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ी है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर हिन्दुस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वहां के लोगों के प्रति भी इनकी दुर्भावना साफा झलकती है क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई डिमांड रखी जाती है, ये साफ इन्कार करते हैं कि इनका ....(**व्यवधान**)...

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : महोदय, कौन यह सब नोट लिख रहा है, कौन जवाब देगा? यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय महंगाई पर चर्चा हो रही है ....(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मिनिस्टर्स बैठे हैं, विलासराव देशमुख जी बैठे हैं, दूसरे मंत्री भी बैठे हैं। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: दो-दो मंत्री बैठे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: ठीक है। आप बोलिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : सर, क्या शरद पवार जी के बदले विलासराव देशमुख जी जवाब देंगे? ...(**व्यवधान**)... क्या आप जवाब देने वाले हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री बी.के. हरिप्रसाद (कर्णाटक) : सरकार जवाब देगी, देशमुख जी नहीं देंगे।

श्री उपसभापति: अब इस पर बहस मत करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : विलासराव देशमुख जी, क्या शरद पवार जी के बदले महंगाई का उत्तर आप देंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठे हैं। वे लिख रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक : माननीय उपसभापति महोदय, आयात एवं निर्यात की जो गलत नीति केन्द्र सरकार की है, उसके कारण भी महंगाई बढ़ी है। समय समय पर कृषि मंत्री जी ने बयान दिया कि हम चीनी का निर्यात करने का काम करेंगे, चीनी के दाम बढ़ने वाले हैं। इससे जमाखोरों का, कालाबाजारियों का ध्यान उस ओर गया और उन्होंने खाद्यान्न सहित चीनी के भारी भंडार इकट्ठा कर लिए जिससे महंगाई बढ़ गई। कृषि मंत्री जी के अलावा यूपीए सरकार के कई जिम्मेदार मंत्रियों ने भी अपने बयानों में कहा कि महंगाई पर अभी दो साल तक काबू नहीं हो पाएगा। महोदय, पूरी की पूरी सरकार महंगाई पर कुछ करने के बजाय, कोई रास्ता निकालने के बजाय केवल घड़ियाली आंसू बहाकर, समय की बात कहकर टालने का काम कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इनकी सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिकी हुई है। वह देश के सामान्य लोगों, गरीबों, दबाए गए, कुचले गए, पिछड़े लोगों की ओर ध्यान देने के बजाय पूंजीपतियों का, बड़े आदमियों का, अमीरों का ध्यान रखने का काम कर रही है। माननीय उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर जो गरीबों की संख्या है, उनके संबंध में बीपीएल का कोटा केन्द्र सरकार तय करती है, यह कोटा कई वर्षों पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा तय किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं। वहां भारी संख्या में गरीबी है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे क्षेत्र हैं जहां पर सूखा और दैवी आपदाएं होती रहती हैं। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने केन्द्र सरकार को बराबर पत्र लिख कर, प्रधान मंत्री जी को पत्र लिख कर बीपीएल के कोटे में बढ़ोत्तरी की मांग की, जिससे गरीबों को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। लेकिन आज तक इस दिशा में केन्द्र सरकार ने न कोई जवाब दिया और न कोई ठोस पहल की। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के मुद्दे पर भी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने वहां के समुचित विकास के लिए तथा गरीबों को ठीक से जीवनयापन करने के लिए अस्सी हजार करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की थी। लेकिन आज तक उस पर केन्द्र सरकार ने कोई समुचित जवाब नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई ही की। माननीय उपसभापति महोदय, यह उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है तो और क्या है? जहां-जहां इनकी सरकारें हैं वहां तो अधिकारिक पैसा देकर वहां के लोगों का ध्यान रखा जा रहा है और वह पैसा भी बिचौलिए के हाथ में बंदर बांट के रूप में जा रहा है। आपके माध्यम से हमारी यह मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बी.पी.एल. गरीबी की रेखा के नीचे लाखों लोग निवास करते हैं, उनकी संख्या की दोबारा सूची बनवा कर जितने भी बी.पी.एल. परिवार रहते हैं, उस सूची के अनुसार उनमें बढ़ोत्तरी की जाए। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने महंगाई को देखते हुए गरीबों को सहूलियतें प्रदान करने के लिए "मुख्य मंत्री महामाया आर्थिक गरीब योजना" प्रारम्भ की है, जिस योजना के माध्यम से हम तीन सौ रुपए प्रति माह प्रत्येक गरीब परिवार को देंगे। हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि यह जरूरी नहीं है कि उसका नाम बीपीएल सूची में हो, यानी जो गरीब होगा उसको हमारी सरकार तीन सौ रुपया प्रति माह देने का काम करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में भी अलग से व्यवस्था की है। माननीय उपसभापति महोदय, एक ओर जहां सीमित संसाधनों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों की हर मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ केन्द्र सरकार गरीबों का कोई ध्यान नहीं रख कर बिचौलियों को, जमाखोरों को, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी वृंदा जी तेल की कीमतों के बारे में चर्चा कर रही थीं। माननीय उपसभापति महोदय, तेल के उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने अपने जो कदम बढ़ाए हैं, तेल के उत्पादन के लिए भी हमने एक प्राइवेट कम्पनी को काम दे रखा है और उस कम्पनी का क्या नाम है, वह सारे के सारे लोग जानते हैं। तेल की

कीमतें क्या होंगी, इसके बारे में समय-समय पर चर्चा होती रहती है। अभी वं्ृदा जी बतला रही थी कि केन्द्र सरकार तेल पर टैक्स के रूप में 34 रुपए लगाने का काम करती है। अगर उन कीमतों को कम करना है तो हमें टैक्स में छूट करनी पड़ेगी, टैक्स कम करना पड़ेगा। जो मूल महंगाई बढ़ती है उसमें तेल की अहम भूमिका है। हमको गरीबों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से यह कह कर नहीं बच सकती कि ग्लोबल महंगाई के कारण, ग्लोबल मन्दी के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। इनको कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा तथा महंगाई पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जमाखोरों पर कंट्रोल करना पड़ेगा।

चीनी के बारे में भी हमारे विद्वान साथियों ने चर्चा की है। माननीय उपसभापति महोदय, चीनी एक ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी के साथ रोजमर्रा की जरूरतों के साथ जुड़ा हुआ है। मात्र चीनी मिलें ही दुनिया में ऐसी मिलें है जिसका कच्चा माल बगैर पैसा लिए और बगैर अग्रिम लिए ही किसान चीनी मिलों के दरवाजों पर फेंकने का काम करते हैं। चीनी बनाने वाले लोग उसके गन्ने का भुगतान 6-6 महीने, 8-8 महीने तक नहीं करते हैं। किसानों को अपने गन्ने के भुगतान के लिए लाठियां भी खानी पड़ती हैं और कई बार गालियों का शिकार भी होना पड़ता है। माननीय उपसभापति महोदय, चूंकि कृषि मंत्री महाराष्ट्र से आते हैं और उनकी चीनी के बारे में अच्छी जानकारी है और यह उनकी विशेष योग्यता भी है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि उनकी जानकारी का लाभ उठाए और गरीबों को सस्ती चीनी उपलब्ध कराए। गरीबों के लाभ उठाने की बजाए पूंजीपति लाभ उठा रहे हैं। माननीय उपसभापति जी, महंगाई के कारण आज आम आदमी, गरीब आदमी की कमर टूट गई है। लोगों के घरों में जहां दो टाइम खाना बनता था, वे अब एक टाइम खाना खाने लगे हैं। पहले गरीब आदमी कहता था कि हम दाल-रोटी खाएंगे, लेकिन अब दाल अस्सी रुपए से सौ रुपए किलो तक बिक रही है, आलू अठारह रुपए किलो तक बिक गया, आटा बीस से पच्चीस रुपए किलो है। गरीब आदमी की रोटी अब उसकी थाली में नहीं है। वह अब चटनी रोटी भी नहीं खा सकता है। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को पूरे देश की भावनाओं का, गरीब लोगों का ध्यान रखते हुए कोई न कोई ठोस उपाय निकालना होगा, जिससे गरीब आदमी भी सांस ले सके। इनको अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना होगा। ये केवल पूंजीपतियों की, जमाखारों की, दलालों की काला बाजारियों के समर्थन में नीतियां बनाने का काम न करें, गरीबों की भी सुनें, तभी देश ठीक ढंग से काम कर सकेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

श्री वृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, एक बड़ी पुरानी कहावत मशहूर है कि "वो क्या जाने पीर पराई, जाके पैर न फटे बिवाई।" आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो महंगाई से अत्यधिक पीड़ित है, परंतु सरकार के पक्ष की तरफ से या जो खाते-पीते बड़े लोग हैं, उनकी तरफ से महंगाई बढ़ने के जो कारण बताए जाते हैं और जिस प्रकार की संवेदनहीनता दिखाई जाती है, उससे हम सबकी चिंता बढ़ जाती है। यह बड़ी विचित्र बात है कि पिछले दो वर्षों से महंगाई रुकने की कब, कौन क्या कहे, महंगाई जहां है, वहां ठहरने का नाम नहीं ले रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसी सदन में हम लोगों ने सात बार से अधिक महंगाई पर चर्चा की, लेकिन वह सारी बहस बांझ निकली, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, उन कदमों का अनुकूल प्रभाव पड़ने की बजाए प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आखिर इसके कारण क्या है? सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि चूंकि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइज बढ़ा दिया, इसलिए Minimum Support Price बढ़ने के कारण चीजों के दाम बढ़ गए। हमने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा दी, लिहाजा क्रय शक्ति बढ़ने के नाते Demand बढ़ गई, इस कारण महंगाई बढ़ गई। यह भी कहा गया कि जो जन प्रणाली नीति है,

उसमें जरूर कोई दोष है। मान्यवर, मैं इन बातों को सही नहीं मानता हूं। यह आधा सच है। असली बात तो महंगाई के संबंध में दो चीजें हैं – एक तो नीतिगत है और दूसरी प्रबंधकीय बात है, कुप्रबंधन है। जिस कुप्रबंधन की तरफ रिजर्व बैंक ने भी इशारा किया, यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष और दूसरे वक्ताओं ने भी उसकी तरफ इशारा किया। जहां तक नीतिगत मामला है, यह बात स्पष्ट है कि आयात और निर्यात की नीति में जो दोष है, जिसकी तरफ माननीय वक्ताओं ने इशारा किया है, वह भी एक बड़ा कारण है। इसका अंदाजा लगाए बिना कि हमारी कितनी आवश्यकता है और कितना उत्पादन है, हम विश्व बाजार के उतार-चढ़ाव को दृष्टि में रखकर निर्यात की छूट दे देते हैं। अभी वृंदा जी ने बताया कि उस पर हम कितने प्रकार की सब्सिडी या कितने प्रकार की incentives देते हैं। जब हमारे यहां माल की कमी होती है, तो विश्व बाजार से ऊंची दरों पर हम चीजों का आयात करते हैं। हमारे यहां गांवों में जो किसान हैं, जो बहुत अर्थशास्त्री नहीं हैं, उनका भी जो सामान्य ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान में वे बरसात के मौसम के पहले अनाज बचा कर रख लेते हैं, जलावन बचा कर रख लेते हैं, क्योंकि अगर बरसात में इन चीजों की आपूर्ति में दिक्कत हो, तो वे उसका मुकाबला कर सकें। परन्तु हमारे यहां इस प्रकार की कोई दृष्टि ही नहीं है कि अगर कोई संकट की घड़ी आए, अभाव की घड़ी आए, अनापूर्ति की घड़ी आए, तो हम उस स्थिति का मुकाबला कैसे करेंगे और उस समय सरकार बिल्कुल असहाय नजर आती है। आयात-निर्यात के संबंध में दोषपूर्ण नीति है।

दूसरी बात यह है कि हमारे जो अर्थ नीति है, जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में हमने जो विकास की पद्धति अपनाई, उसी विकास की पद्धति अपने का नतीजा है कि हमारे विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वह प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वह सेकंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर हो, इनमें संतुलन नहीं है। इस असंतुलन के कारण भी हमारी स्थिति दयनीय बन गई है और महंगाई को रोक पाने में हम असफल हैं। आप जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि आता है। हमारी विकास दर 8 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत बताई जा रही है और हम बड़ी डींग हांकते हैं कि कुछ दिनों में हमारी विकास दर 9 प्रतिशत हो जाएगी, परन्तु उस विकास दर के अनुपात में कृषि क्षेत्र की विकास दर 4 प्रतिशत होनी चाहिए। परन्तु आज वह क्या है? आज कृषि की विकास दर 4 प्रतिशत के बजाए 1.5 प्रतिशत ही है। अब आप देखिए कि जो निर्माण क्षेत्र है, उसमें यह 8 प्रतिशत है, जो सेवा क्षेत्र है, उसमें 14 प्रतिशत, 15 प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र में विकास दर बढ़ रही है, निर्माण क्षेत्र में विकास दर बढ़ रही है, मगर जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र के विकास दर के कम होने के कारण जो असंतुलन पैदा हुआ है, वह भी महंगाई का बहुत बड़ा कारण होता है।

तीसरी बात यह है कि हमने globalization और privatization की जो नीति अख्तियार की, उससे हम बाजार की शक्तियों पर आश्रित हो गए। बाजार की शक्तियों पर control किसका है? इस पर सरकार का भी control नहीं रह गया। बाजार की शक्तियों पर जो ताकतवर लोग हैं, जो धनी वर्ग है, जो औद्योगिक घराने हैं, जो सटोरिए हैं, जो जमाखोर हैं, उनका कब्जा हो गया। जब बाजार पर इनका कब्जा हो गया और आप बाजार की शक्तियों पर आश्रित हो गए, लिहाजा बाजार का उतार-चढ़ाव होता रहता है और सरकार तमाशबीन बन कर, असहाय बन कर देखती रहती है, इसलिए कोई control नहीं हो पाया। उसके साथ-ही-साथ यह सही है कि हमारे देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, परन्तु क्रय शक्ति किसकी बढ़ी है? आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है। सरकार अभी यही नहीं तय कर पाई है कि गरीब कितने हैं, गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या क्या है, क्योंकि एक तरफ सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है, तो दूसरी तरफ तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट है। अगर मोटे तौर पर इन रिपोटों की संस्तुतियों पर विचार करें, तो ये भी मानते हैं कि देश के अन्दर 77 फीसदी-80

फीसदी आदमी ऐसे हैं, जो 20 रुपए से कम पर अपना गुजारा कर रहे हैं या खर्च करते हैं। अगर सवा सौ करोड़ की इतनी बढ़ी आबादी में से तीन-चौथाई जनसंख्या बीस रुपये से भी कम पर अपना खर्च चलाती है और आप यह तर्क देते हैं कि उनकी क्रय शक्ति बढ़ गई है, तो हमें सिवाय आपकी बुद्धि पर तरस आने के और कुछ नहीं होता है। हां, यह सही है कि छठे वेतन आयोग के ज़रिए लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, इसके साथ ही देश के अन्दर भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है, काला पैसा बढ़ गया है, मार्किट में ईज़ी मनी आ गई है, जिसके नाते उनकी क्रय शक्ति बढ़ गई और वे बाजार को प्रभावित कर रहे हैं।

कल ही मैं नौएडा की तरफ गया, वहां पर एक 18 सैक्टर का इलाका है। लोगों ने मुझे बताया कि जो सामान दिल्ली में एक रुपये में मिलता है, वही 18 सैक्टर के बाजार में 100 रुपए में मिलता है। इतना अधिक फर्क है। हमारे एक मित्र रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने बताया कि मैंने पांच सौ रुपये महीने पर एसडीएम की नौकरी शुरू की थी, लेकिन आज हमें पचास हजार रुपय पैंशन मिलती है। इस तरह एक वर्ग वह है, जिसकी पैंशन्स बढ़ गईं, तन्ख्वाहें बढ़ गईं, जिसके पास ईज़ी मनी का साधन है, जो काला पैसा पैदा कर सकता है और जिसके पास अकूत चल एवं अचल सम्पत्ति है। उसके ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं होता। महंगाई की मार तो उस गरीब पर पड़ती है, उस छोटे कर्मचारी पर पड़ती है, अध्यापक पर पड़ती है, जिसका वेतन बंधा हुआ है, जिसके पास बाहर की कमाई का कोई साधन नहीं है।

चौथी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में हमने मॉल्स, असैंशियल कमॉडिटी शॉप्स एवं रिटेल शॉप्स की एक चेन खड़ी कर दी है। आप अगर खुदरा बाजार अथवा छोटे बाजार में जाइए तो उन चीजों के दाम कम हैं, परन्तु वहीं आप किसी मॉल में चले जाइए, रिटेल शॉप्स में चले जाइए, जहां दाम आसमान को छूते हैं। इनके मालिक कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं हैं, बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, साथ ही सरकार उनको नाना प्रकार की छूट भी दे रही है। ऐसे लोग भी बाजार की चीजों के दाम तय करते हैं। उनके अपने बड़े-बड़े गोदाम हैं और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कोई इंस्पैक्टर उनके गोदाम पर या उनकी दुकानों पर छापा नहीं मार सकता या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसे लोग भी अपने तरीके से चीजों के दाम बढ़ाते हैं और साथ ही जमाखोरी भी करते हैं।

अभी पहले भी हमने जिक्र किया कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के जरिए तनख्वाहें बढ़ गई हैं और एक लाख, दो लाख, दस लाख, बीस लाख तक के पैकेज आ गए हैं। जिनके पास दस-दस लाख या बीस-बीस लाख के पैकेज आ रहा है और जो बड़ी-बड़ी मल्टीनैशनल कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से एक प्रकार से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हो रहा है।

मान्यवर, यह आम बात है कि अगर चीजों का उत्पादन नहीं बढ़ता, अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ता है, लेकिन एक वर्ग विशेष की खरीदने की ताकत बढ़ती है, उसकी जेब में पैसा आता है, तो यह स्वाभाविक है कि उस वर्ग की खपत बढ़ जाती है। उत्पादन यथावत रहा और खपत बढ़ती गई, तो आखिर वह किसका हिस्सा लेगा और किसकी थाली की रोटी छीनेगा? गरीब की ही तो छीनेगा न। इसी को झपटती वृत्ति, झपट्टा मार वृत्ति या हिस्सा मार वृत्ति भी कहते हैं। झपट्टा कौन मारता है? हिस्सा कौन मारता है? जो ताकतवर होता है, चालाक होता है, जिसकी जेब में पैसा होता है, वही गरीब का हिस्सा मारता है। यह महंगाई रोग का लक्षण है, रोग नहीं है और हमारा अर्थ संचालन

उसी का नतीजा है, लेकिन हम बुनियादी नीतियों पर विचार करने के बजाय, उसके दूरगामी नतीजों पर विचार करने के बजाय अथवा उसका स्थायी हल ढूंढने के बजाय छोटे-मोटे हल ही ढूंढते हैं, जिसमें से भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ नहीं निकलता है।

अब पीछे हल्ला किया गया कि हम किसानों के लिए सपोर्ट प्राइज़ बढ़ा दिया है, इस संबंध में मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा कि आपने जो सपोर्ट प्राइज़ बढ़ाया, उसमें से किसान को कितना मिला? आप यह समझिए कि जो paddy है, धान है, सरकार ने उसका दाम 950 रुपए प्रति क्विंटल तय किया और एक क्विंटल धान में से अगर 67 किलो चावल हुआ तो उसकी कीमत कितनी हुई? 14 रुपए 18 पैसे प्रति किलो। यही 14 रुपए 18 पैसे किसान को मिले। अगर बाजार की retail price को देखा जाए तो वह दिसम्बर 2007 में 16 रुपए, दिसम्बर, 2008 में 22 रुपए और दिसम्बर 2009 में 23 रुपए प्रति किलो थी। effective price released by farmers at MSP अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर पर किसानों को मिलने वाला वास्तविक मूल्य क्या है? के अनुसार किसान को क्या मिला? उसे 2007 में 11 रुपए 12 पैसे, 2008 में 13 रुपए 43 पैसे और 2009 में 14 रुपए 18 पैसे मिले। इस प्रकार बाजार में जो retail price है और किसानों को जो मिला, उसमें यह फर्क है तथा इसके अतिरिक्त बाजार में जो चोर बाजारी और टैक्स आदि है, तो इसके नाते यह तर्क भी बेमतलब है कि किसानों को MSP बढ़ाने के कारण चीजों के दाम बढ़ें।

महोदय, वही हालत गन्ने में भी है। आपने जो गन्ने का थोक मूल्य बढ़ाया, उसमें गन्ने की पेराई से जितनी चीनी बनी, किसान को उसकी कीमत 14 रुपए 45 पैसे की दर से ही मिली और आज बाजार में चीनी का भाव क्या है? मुझे यह बताया गया कि इस बार चीनी के मिल मालिकों ने जो मुनाफा कमाया उतना मुनाफा उन्होंने पिछले 70 वर्षों में भी नहीं कमाया था। मुझे यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग से संबंधित एक उद्योगपति समूह ने इस सत्र में एक हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। अभी महाराष्ट्र में 72 हजार 684.3 मीट्रिक टन चीनी थी, जो लोगों को सस्ती दरों पर बेचने के लिए थी, लेकिन महाराष्ट्र के जो चीनी के बड़े-बड़े barrens थे, मालिक थे, उन्होंने उसे खुले बाजार में बेच दी। यह खबर समाचार पत्रों में छपी। अब यह सरकार कितनी संवेदनहीन है कि ...(**समय की घंटी**)... प्रधान मंत्री ने महंगाई पर विचार विमर्श करने के लिए जो बैठक बुलाई, प्रधान मंत्री की उस बैठक में इसकी चर्चा तक नहीं हुई। यह कितनी गम्भीर बात है? अगर अखबारों में यह खबर छपी तो यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि 72 हजार 684.3 मीट्रिक टन चीनी जो कि जनवितरण प्रणाली के लिए थी, वह जनवितरण प्रणाली वाली चीनी खुले बाजार में बिक जाए। अगर यह खबर गलत है तो उस अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए, उसे नोटिस भेजी जानी चाहिए और अगर वह सही है तो इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई हो। ठीक ही कहा वृंदा कारत जी ने...

श्री उपसभपति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बृजभूषण तिवारी : मान्यवर, मैं बस एक-दो मिनट में अपनी बात खात्म करना चाहता हूं।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह मुनाफा केवल व्यापारी या उद्योगपति ही नहीं कमाते बल्कि यह सरकार भी कमाती है। सरकार मुनाफा क्यों कमाती है? क्योंकि सरकार का अनाप-शनाप का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। सरकार अपने खर्चे में, अपने ठाट-बाट में, अपने शानो-शौकत में और अपनी फिजूलखर्ची में किसी प्रकार की कोई कटौती करना नहीं चाहती है। सरकार का खर्चा बढ़े और उसकी आय के स्रोत न बढ़ें तो सिवाय हमारी हड्डी से हमारा खून निकालने के, हमारा खून चूसने के या गरीब की जान लेने के उसके सामने अन्य कोई रास्ता नहीं है।

जिस तरीके से आप वकील की तरह बहस करते हैं, एक कहावत है कि "रोम जल रहा था और नीरो चैन की बंसी बजा रहा था।" कल ही बात हो रही थी। जब कहा गया कि इस महंगाई से आम आदमी पीड़ित है तब सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि नहीं, आम आदमी पीड़ित नहीं है। तो फिर कौन पीड़ित है? ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : ऐसा किसी ने नहीं कहा ...(**व्यवधान**)...

श्री बृजभूषण तिवारी : ऐसा कहा गया। यह कहा गया और हम लोगों ने सुना। इस प्रकार की संवेदनहीनता सरकार दिखाती है मेरा कहना है कि जब तक दाम नीति तय नहीं होती है, दाम नीति का मतलब है - उत्पादन-लागत। उत्पादन-लागत तय करने में पारदर्शिता (transparency) होनी चाहिए, cost accountability धोखा है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो दाम-नीति चल रही है, यह अंग्रेजों के जमाने की दाम-नीति है। अंग्रेजी राज़ में उनकी यह नीति थी कि वे हमारी खेती को कमजोर करें हमारे आर्थिक ढांचे को कमजोर करें और उनका जो औपनिवेशिक शोषण है, वह चलता रहे। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : समाप्त कीजिए, एक बज गये।

श्री बृजभूषण तिवारी : सर, एक सेकंड। इसीलिए अनाज के दाम तय करने की जिम्मेदारी सरकार - अंग्रेजों ने ले ली और औद्योगिक उत्पादन के दाम को तय करने की जिम्मेदारी उन्होंने उनके निर्माताओं को दे दी। आज भी आजादी के बाद हम चाहते हैं कि इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए। अगर कारखाने का मालिक अपने कारखाने की बनी चीजों के दाम तय कर सकता है तो किसान अपने अनाज का दाम क्यों नहीं तय कर सकता? औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन के दामों में अगर समानता नहीं है, अगर किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, अगर खेती में निवेश नहीं बढ़ेगा, अगर खेती की विकास-दर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो हम खाद्य-सुरक्षा कैसे हासिल कर सकते हैं?

श्री उपसभापति : तिवारी जी, समाप्त कीजिए।

श्री बृजभूषण तिवारी : सर, मैं बताना चाहता हूं कि देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बजट का आधे से ज्यादा पैसा केवल खाने का खर्च होता है। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार केवल बहस के लिए बहस कराकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री न समझे। अगर यह महंगाई पर रोक नहीं लगाएगी तो मैं उनको संकेत की तरह बता देना चाहता हूं कि वह नारा फिर गूंजेगा कि

"जब तक भूखा इंसान रहेगा,

धरती पर तूफान रहेगा"।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MESSAGES FROM LOK SABHA

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Messages from Lok Sabha.

(I) **Nomination of Members to the Committee on Public Accounts.**

(II) **Nomination of Members to the Committee on Public Undertakings.**

(III) **Nomination of Members to the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.**